

मुकदमों का विवरण

मरियप्पन

बनाम

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा (2023 की आपराधिक अपील संख्या 3598) 24 नवंबर, 2023

[विक्रम नाथ और राजेश बिंदल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: घटना के दिन दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। झगड़े के दौरान, आरोपी नं। 1 और 2 पीड़ित को सूरिक्निव्स से कई बार चाकू मारा गया, जबकि आरोपी नं। 3, हालांकि एक कुदाल के हैंडल के साथ सशस्त्र, चोटों को नहीं भड़काया लेकिन हमले में सुविधा प्रदान की। अपीलार्थी-अभियुक्त को यू/एस दोषी ठहराया गया था। 302 भारतीय दंड संहिता . क्या अभियुक्त के कार्य अपवाद 4 से एस के अंतर्गत आएंगे। 300 भारतीय दंड संहिता सी. या गैर-इरादतन हत्या का कार्य दंडनीय यू/एस होगा। 302.

दंड संहिता, 1860 -एस. 303 और एस. 304 भाग-I-विचारण विचारण न्यायालय ने गवाहों और भौतिक साक्ष्य की जांच करने के बाद, दोषी अपीलार्थी-अभियुक्त सं। 1 को धारा 302 भारतीय दंड संहिता सी. और आरोपी एन. ओ. एस. को बरी कर दिया। 2 और 3 उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से-उच्च न्यायालय ने यू/एस के तहत दोषसिद्धि के आदेश को स्वीकार कर लिया। 302 भारतीय दंड संहिता सी. का-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: शुरुआत से ही, यानी एफ. आई. आर. में स्थापित अभियोजन पक्ष की कहानी यह थी कि शुरू में पक्षों के बीच गरमागरम चर्चा हुई और गुस्से में शारीरिक हमला हुआ-यहां तक कि मौखिक गवाही भी उसी प्रभाव के लिए है-हालांकि उसी साक्ष्य पर विचारण न्यायालय ने दो सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया है और केवल अपीलार्थी को दोषी ठहराया है-यह भी सबूत में आया है कि अपीलार्थी ने केवल एक चोट पहुंचाई थी जबकि अन्य अभियुक्तों ने कई चोटें पहुंचाई थीं-हालांकि, विचारण न्यायालय ने अन्य दो अभियुक्तों को बरी कर दिया-अपीलार्थी और मृतक के बीच पिछली दुश्मनी मौखिक विवाद का कारण बनी थी, लेकिन यह अभियुक्त के लिए पूर्व नियोजित घातक घटना को अंजाम देने का कारण नहीं था।

1074

मरियप्पन बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा 1076

वर्तमान मामले में यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का प्रत्यक्ष कार्य एक भावुक मौखिक झगड़े की गर्मी में गुस्से के दौरान हुआ था और यह अपवाद 4 से

एस के अंतर्गत आता है।³⁰⁰ भारतीय दंड संहिता सी.-यू/एस. द्वारा दोषसिद्धि।³⁰² भारतीय दंड संहिता सी. को एस. में परिवर्तित किया जाता है।³⁰⁴ भाग-I भारतीय दंड संहिता सी. [पैरा 11,12 और 13]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

रामपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 8 एस. सी. सी. 289:[2012] 7 एससीआर 160;

सुरिंदर कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ (1989) 2 एस. सी. सी. 217:[1989] 1 एस. सी. आर. 941-पर निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील No.3598।

2013 के सी. आर. एल. ए. No.151 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 22.04.2016 से।

रूप:

टी. हरीश कुमार, नवनीत दुगर, सुभम कोठारी, सुश्री प्रीति, जी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री शुभी भारद्वाज, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निर्णय/आदेश

विक्रम नाथ, जे।

1. यह अपील 2013 की आपराधिक अपील में मद्रास में उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 3 की शुद्धता पर जोर देती है, जिसमें उच्च विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया है और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 301 के अंतर्गत दोषसिद्धि के आदेश और निचली अदालत द्वारा पारित आजीवन कारावास की सजा को स्वीकार किया है।

1 भारतीय दंड संहिता

/

[2023] 15 एस सी आर।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 इस मामले में वर्तमान अपीलार्थी द्वारा की गई गैर-इरादतन हत्या शामिल है। वर्तमान अपीलार्थी अभियुक्त नं.1 भवानी में विद्वत चतुर्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, इरोड जिले के निर्णय पर 2010 के S.C.No.177 में विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष। जबकि अन्य दो अभियुक्तों ने, यानी, अभियुक्त संख्या 12 और 3 को विचारण न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। 2.2 इस मामले में एक कोलंडाईप्पम की हत्या शामिल है, जिसमें मुख्य उद्देश्य की पहचान मृतक और तीन अभियुक्तों के बीच भूमि विवाद को लेकर लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के रूप में की गई थी। घटना से पहले, कई टकराव और धमकियां थीं, विशेष रूप से साढ़े तीन साल पहले विवादित भूमि पर, और उसके बाद मृतक की पत्नी और पहले आरोपी की बहन, पाप्पा के बीच झगड़ा हुआ था। मृतक की पत्नी द्वारा पुलिस द्वारा समझौता की गई शिकायत सहित इन घटनाओं ने शत्रुता को तेज कर दिया।

2.3 17 मार्च 2009 को, लगभग 6:00 दोपहर में, नेरिंगिपेट्टई गाँव के कोइल काडु चिथानट्टू सलाई में, मृतक का, <ID1,3 और 5 के साथ, अभियुक्तों द्वारा सामना किया गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। झगड़े के दौरान, आरोपी नं.1 और 2 ने कोलंडाईप्पम को सूरी-चाकू से कई बार चाकू मारा, जबकि आरोपी नं.3, हालांकि एक कुदाल के हैंडल के साथ सशस्त्र, चोटों को नहीं भड़काया लेकिन हमले में सुविधा प्रदान की। मृतक की बेटी पी. डब्ल्यू. 1 ने इस घटना को देखा। हमले के बाद, मृतक को भवानी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉ. (श्रीमती) जनता ने उसे मृत घोषित कर दिया और अम्मापेट्टई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिससे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 और 324 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

2.4 शुरुआत में सुब्बैया (P.W.13) और बाद में ए. राजेंद्रन (P.W.14) के नेतृत्व में की गई जांच में सबूतों का सावधानीपूर्वक संग्रह शामिल था। इसमें अपराध स्थल से रक्तरंजित मिट्टी, एक अवलोकन मजार और एक रफ स्केच की तैयारी और हत्या के हथियारों की बरामदगी शामिल थी। डॉ. पूर्णचंद्रिका (पी. डब्ल्यू. 8) द्वारा किए गए शव परीक्षण में मौत के कारण के रूप में कई छुरा घोंपने के घावों का पता चला, विशेष रूप से हृदय में एक घातक चोट को ध्यान में रखते हुए।

2.5 अपीलार्थी के अपराध में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य में उसके स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के बाद हत्या के हथियार (एक सूरी-चाकू) और खून से सने कपड़ों की बरामदगी शामिल है। इसके अतिरिक्त, 1077 की गवाही

मरियप्पन बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा [विक्रम नाथ, जे.] 1078

प्रत्यक्षदर्शी, विशेष रूप से पीडब्लू. 1, और भौतिक वस्तुओं से रक्त समूह को मृतक से जोड़ने वाले फोरेंसिक साक्ष्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रत्यक्षदर्शी विवरणों में कुछ विसंगतियों के बावजूद, भारी सबूत ने आरोपी नं.1 'हमले में प्रत्यक्ष भागीदारी'। 2.6 प्रत्यर्थी

पुलिस द्वारा आरोप पत्र जारी किए जाने के बाद, 2010 के S.C.No.177 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भवानी के समक्ष एक सत्र मामला दर्ज किया गया था। विचारण न्यायालय ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए दो आरोप विरचित किए। अभियुक्त Nos.1 के खिलाफ आरोप भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ धारा 302 के अंतर्गत लगाया गया था। आरोपी नं. के खिलाफ आरोप था। 3 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत।

2.7 मुकदमे में 14 गवाहों से पूछताछ की गई और 18 दस्तावेजों और 9 भौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत किया गया। जबकि आरोपी नं.2 और 3 को उनके खिलाफ निर्णायक सबूत की कमी के कारण बरी कर दिया गया, आरोपी नं.1, अर्थात्, इसमें अपीलार्थी को गवाही के भार और अन्य दस्तावेजी और भौतिक साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया गया था। विचारण न्यायालय के अनुसार ठोस सबूत थे, विशेष रूप से हत्या के हथियार की बरामदगी और चश्मदीद गवाहों की गवाही की निरंतरता, जिसने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को विधिवत साबित किया।

3. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, दिनांक 05.10.2012 के निर्णय द्वारा, विचारण न्यायालय ने आरोपी नं.1, अर्थात्, अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत अपील करता है और आरोपी Nos.2 और 3 को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर देता है। अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 5,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई, अन्यथा उक्त अपराध के लिए एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

4. अपीलार्थी ने मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 की आपराधिक अपील का नेतृत्व किया। आदेश डी. टी.22.04.2016, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और अपीलार्थी की अपील को इस निष्कर्ष पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थी का कार्य पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के तीसरे अंग के भीतर आएगा और यह भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के किसी भी अपवाद के अंतर्गत नहीं आएगा और इसलिए वह भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। 5. अपीलार्थी ने 2013 की आपराधिक अपील संख्या 151 में उच्च विचारण न्यायालय के उपरोक्त आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील का नेतृत्व किया है, जिसमें अन्य आधारों के साथ-साथ दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करने का अनुरोध किया गया है, कि विचारण विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त नं.1, अचानक, जबकि शाब्दिक झगड़ा

/

[2023] 15 एस सी आर।

जो चल रहा था, उसने मृतक को अपनी बेटी, बेटे, उसके रिश्तेदारों के सामने चाकू मार दिया था और इसलिए उसका कार्य भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के

अंतर्गत आना चाहिए और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग 1 का दोषी होगा और उसी के अनुसार सजा दी जानी चाहिए।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वकील ने अपीलार्थी की दलीलों का विरोध करते हुए निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों का समर्थन किया।

7. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हम मानते हैं कि विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और मामले के तथ्य और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से उचित संदेह से परे स्थापित करती हैं कि अपीलार्थी द्वारा किया गया घाव मृतक की मृत्यु का कारण था। उच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी को भी दोहराया कि अपीलार्थी द्वारा चाकू से की गई चोट मृतक की मृत्यु का कारण थी।

8. इसलिए एकमात्र प्रश्न जो हमारे सामने विचार के लिए बचा है, वह यह है कि क्या अभियुक्त का कार्य गैर-इरादतन हत्या है या नहीं। दूसरे शब्दों में, प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त का कार्य भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा या धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय हत्या के बराबर गैर-इरादतन हत्या का कार्य होगा।

9. रामपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2 के मामले में इस न्यायालय ने

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग 1 के अंतर्गत अपराध ने गैर इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच के अंतर पर विस्तार से चर्चा की है। जो माना जाता है वह यह है कि वर्गीकरण तथ्य की बात होगी जो मुकदमे में दिए गए साक्ष्य पर निर्भर करती है। मोटे तौर पर, जिन कारकों पर विचार किया जाना है, वे इसके पैराग्राफ 25 में गिने गए हैं। उसी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“25. जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, धारा 304 के किसी भी भाग में एक ऑफ-एनस का वर्गीकरण मुख्य रूप से तथ्य की बात है। इसका निर्णय आक्रमण की प्रकृति, आक्रमण करने के इरादे, इस्तेमाल किए गए हथियार, चोटों के स्थान और प्रकृति, पूर्व नियोजित दिमाग का अस्तित्व, अपराध करने में भाग लेने वाले व्यक्तियों और कुछ हद तक अपराध करने के उद्देश्य के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इन सभी परिस्थितियों के संदर्भ में पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य

2 (2012) 8 एससीसी 289 1079

मरियप्पन बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा [विक्रम नाथ, जे.] 1080

न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में बहुत मदद मिलती है कि संहिता के किस दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत आरोपी को दंडित किया जा सकता है। इसे एक अन्य दृष्टिकोण से भी तय किया जा सकता है अर्थात् "बहिष्करण के सिद्धांत" को लागू करके। इस सिद्धांत को निर्धारण की दो-चरणीय प्रक्रिया का सहारा लेते हुए लागू किया जा सकता है। सबसे पहले, न्यायालय एक प्रारंभिक कार्रवाई दर्ज कर सकता है यदि अभियुक्त ने संहिता की धारा 302

के मूल प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया था, अर्थात् "गैर-इरादतन हत्या"। फिर दूसरा, यह जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है कि क्या मामला संहिता की धारा 300 में विस्तृत किसी भी अपवाद में आता है। यह दोगुना सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय द्वारा लिया गया निष्कर्ष तथ्यों पर सही है और विधि में पोषणीय है। हम इस तरह के प्रस्ताव को यह इंगित करने के लिए कह रहे हैं कि इस तरह का निर्धारण आपराधिक न्याय वितरण के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्दोषता का अनुमान और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र का सार है और इन्हें अभियुक्त के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया जाता है। "

10. यहाँ सुरिंदर के फैसले का उल्लेख करना भी उचित होगा।

कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ **3**, जिसमें इस न्यायालय ने फैसला सुनाया था।

आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए आधार: "7. इस अपवाद को लागू करने के लिए चार आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (i) यह अचानक हुआ था; (ii) कोई पूर्वधारणा नहीं थी; (iii) यह कार्य जुनून की गर्मी में किया गया था; और (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से कार्य नहीं किया था। झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है, यह प्रासंगिक नहीं है कि उकसावे को किसने भड़काया या हमला शुरू किया। घटना के दौरान हुए घावों की संख्या एक निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि घटना अचानक और पूर्व नियोजित नहीं हुई होगी और बंद करने वाले ने गुस्से में काम किया होगा। बेशक, बंद करने वाले ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया होगा या क्रूर तरीके से काम नहीं किया होगा। जहाँ, अचानक झगड़े पर, क्षण की गर्मी में एक व्यक्ति एक हथियार उठाता है जो उपयोगी होता है और चोट पहुँचाता है, जिसमें से एक घातक साबित होता है, वह इस अपवाद के लाभ का हकदार होगा बशर्ते उसने क्रूरता से काम न लिया हो। "

3 (1989) 2 एससीसी 217

/

[2023] 15 एस सी आर।

11. वर्तमान मामले में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी ने अचानक मृतक को उसके साथ तीखी बहस के दौरान चाकू मार दिया था, न कि एक पूर्व नियोजित हमले के दौरान जो मृतक की मौत का कारण बनने के एकमात्र इरादे से किया गया था। अपीलार्थी और मृतक के बीच पिछली शत्रुता मौखिक विवाद का कारण बनी, लेकिन यह आरोपी द्वारा मृतक के खिलाफ पूर्व नियोजित घातक हमले को अंजाम देने का कारण नहीं था। अपीलार्थी ने जुनून की गर्मी में और मृतक को मारने के लिए पूर्व नियोजित दृष्टिकोण के बिना "अचानक" काम किया था।

12. शुरू से ही यानी एफ. आई. आर. में स्थापित अभियोजन पक्ष की कहानी यह थी कि शुरू में पक्षों के बीच गरमागरम चर्चा हुई थी और गुस्से में शारीरिक हमला हुआ था। यहां तक कि नेत्र साक्ष्य भी उसी प्रभाव को दर्शाता है। यद्यपि समान साक्ष्य पर विचारण विचारण न्यायालय ने दो सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया है और केवल अपीलार्थी को दोषी ठहराया है। यह भी सबूत में आया है कि अपीलार्थी ने केवल एक चोट पहुंचाई थी जबकि अन्य अभियुक्तों ने कई चोटें पहुंचाई थीं। हालांकि, विचारण न्यायालय ने अन्य दो अभियुक्तों को बरी कर दिया।

13. इसलिए, वर्तमान मामले में दिए गए साक्ष्य से यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृतक की हत्या का अपीलार्थी का स्पष्ट कार्य एक भावुक मौखिक झगड़े की गर्मी में गुस्से में हुआ था और यह भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा गैर इरादतन हत्या को साबित करने के लिए आवश्यक स्पष्ट इरादे को भी स्थापित नहीं किया गया है।

14. अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

15. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि को धारा 304 भाग-1 में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें 10 साल की कठोर कारावास और 5 लाख रुपये की सजा है। 50,000/- का भुगतान पीड़ित परिवार को किया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

अंकित ज्ञान